



कर्नाटक का अंधवश्वास वरिधी अधनियिम

प्रीलमिस के लयि:

कर्नाटक का अंधवश्वास वरिधी अधनियिम

मेन्स के लयि:

भारत में अंधवश्वास संबन्धी कुपरथाएँ

चर्चा में क्योँ?

- कर्नाटक सरकार ने 4 जनवरी, 2020 को औपचारिक रूप से 'अमानवीय प्रथाओं तथा काला जादू की रोकथाम और उन्मूलन अधनियिम, 2017, (Karnataka Prevention and Eradication of Inhuman Evil Practices and Black Magic Act, 2017) को अधसूचित कयि।

मुख्य बदि:

- यह वविदास्पद अंधवश्वास वरिधी अधनियिम वर्ष 2017 में पारति कयि गया था इसे 6 दसिंबर, 2017 को राज्यपाल की अनुमतिप्राप्त हुई तथा वर्तमान सरकार द्वारा 4 जनवरी, 2020 को औपचारिक रूप से अधसूचित कयि गया।
- इस अधनियिम को राज्य के समाज कल्याण वभिग द्वारा संचालति कयि जा रहा है।

अधनियिम की पृष्ठभूमि:

- इस अधनियिम को वर्ष 2013 में 'कर्नाटक अंधवश्वास वरिधी वधियक, 2013' (Karnataka Anti Superstition Bill, 2013) के रूप में लाया गया था।
- नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी (National Law School of India University- NLSIU) के एक वशिषज्ञ पेनल ने सामाजिक बहिष्कार और समावेशी नीतिपर अधययन करते हुए वर्ष 2013 में पहली बार इस कानून का मसौदा वधियक पेश कयि जसिमें एक दर्जन से अधिक अंधवश्वासों को रेखांकति कयि गया।
- हालाँकि मसौदे के सार्वजनिक होने के बाद कई वपिक्षी दलों ने इसका धार्मिक आधार पर वरिध कयि।
- धार्मिक नेताओं और राजनीतिक दलों द्वारा वरिध कयि गए शुरुआती मसौदे में नमिनलखिति प्रथाओं पर प्रतबिध लगाए गए थे-
 - पुजारियों को पालकी में ले जाना।
 - धर्मगुरुओं की चरण-वंदना करना।
 - मदे स्नान को रोकना।
 - वासतु, ज्योतिष और हस्तरेखा वजिज्ञान पर प्रतबिध।

मदे स्नान

(Made Snana):

यह दक्षिण कन्नड़ क्षेत्र में प्रचलति एक परंपरा है जहाँ श्रद्धालु अपनी मनौतियों को पूरा करने के लयि उच्च जातियों द्वारा खाए गए भोजन के अवशेषों पर लोटते हुए स्नान करते हैं।

- वर्ष 2014 और 2016 में राज्य सरकार द्वारा लाए गए वधियक के मसौदों को भी वरिध का सामना करना पड़ा।

वर्तमान अधिनियम:

- अंततः वर्ष 2017 में राजनीतिक तौर पर सर्वसम्मतिवाला एक वधियक तैयार किया गया।
- इस अधिनियम में धार्मिक स्थानों पर वास्तु, ज्योतिषि, प्रदक्षिणा या पवित्र स्थानों की परकिरमा संबंधी कार्यों को बाहर रखा गया है।
- 'मदे स्नान' की प्रक्रिया को इस अधिनियम के तहत स्वैच्छिक कर दिया है तथा बचे हुए भोजन को इस प्रक्रिया में शामिल नहीं करने के लिये इसे संशोधित किया गया है।
- वर्ष 2017 के इस अधिनियम के तहत कुल 16 प्रथाओं पर प्रतिबंध लगाया गया है, जिनमें से कुछ प्रमुख प्रथाएँ नमिनलिखित हैं-
 - महिलाओं के मासिक धर्म के दौरान पूजा घरों और घरों में उनकी आवाजाही पर प्रतिबंध लगाना।
 - लोगों को आग पर चलने के लिये मजबूर करना।
 - लोगों को दुष्ट घोषित करके उनकी पटिाई करना।

सज़ा का प्रावधान:

- यह अधिनियम न्यूनतम एक वर्ष से अधिकतम सात वर्ष तक के कारावास तथा न्यूनतम पाँच हजार से अधिकतम पचास हजार रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान करता है।
- इस कानून को राज्य पुलिस द्वारा पुलिस स्टेशनों में सतर्कता अधिकारियों की नयिकृति के साथ लागू किया जाना है।

क्यों महत्त्वपूर्ण है यह अधिनियम?

- कुछ लोगों का मत हो सकता है कि प्रस्तावित कानून संविधान के अनुच्छेद 25 (प्रत्येक व्यक्तिको अन्तःकरण की स्वतंत्रता और धर्म को अबाध रूप में मानने, आचरण करने तथा प्रचार करने का अधिकार) का उल्लंघन करता है। हालाँकि इसे एक उचित प्रतिबंध के रूप में देखा जाना चाहिये, क्योंकि इससे सार्वजनिक हित सुनिश्चित होता है।
- कर्नाटक में इस कानून को मज़बूती से लागू करने के लिये राज्य सरकार गंभीर है। कुप्रथाओं के उनमूलन में कानूनी प्रावधानों की उपयोगिता अवश्य है, लेकिन समाज से अंधविश्वासों को जड़ से समाप्त करने के लिये पर्याप्त नहीं है। इसके लिये हमें शिक्षा, तर्कसंगत सोच और वैज्ञानिक चिंतन को बढ़ावा देना होगा।

आगे की राह:

- अल्पावधिक सुधारों के लिये हमें ऐसे कानूनों की आवश्यकता है जो इन कुरीतियों का अंत करने में सहायक हों।
- कुप्रथाओं के दीर्घकालिक सुधार हेतु शिक्षा, तर्कसंगत सोच और वैज्ञानिक चिंतन को बढ़ावा देना होगा।

प्राचीनकाल से ही दुनिया भर में अंधविश्वास व्याप्त रहा है। अंधविश्वास एक तर्कहीन विश्वास है जिसका आधार अलौकिक प्रभावों की मनगढ़ंत व्याख्या है। इन अंधविश्वासों पर अधिकांश भारतीयों का अत्यधिक विश्वास है जो प्रायः आधारहीन होते हैं।

स्रोत- इंडियन एक्सप्रेस